

EXAM GENIUS

— Presents —

GENIUS CURRENT AFFAIRS

In Bilingual
15 & 16 February 2026



 UPSC

 SSC

 BANK

 RAILWAY

Achieve Success with Exam Genius - Your Ultimate Guide to Reasoning Mastery !



Ques: As per RBI's draft directions, what action must banks take if mis-selling is established?

RBI के ड्राफ्ट निर्देशों के अनुसार, यदि गलत बिक्री (Mis-selling) साबित होती है तो बैंक को क्या करना होगा?

- A) Issue warning to employee only / केवल कर्मचारी को चेतावनी देना
- B) Pay 10% penalty to RBI / RBI को 10% जुर्माना देना
- C) Refund full amount and compensate for loss / पूरी राशि वापस करना और नुकसान की भरपाई करना
- D) Close customer's account / ग्राहक का खाता बंद करना
- E) No action required / कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

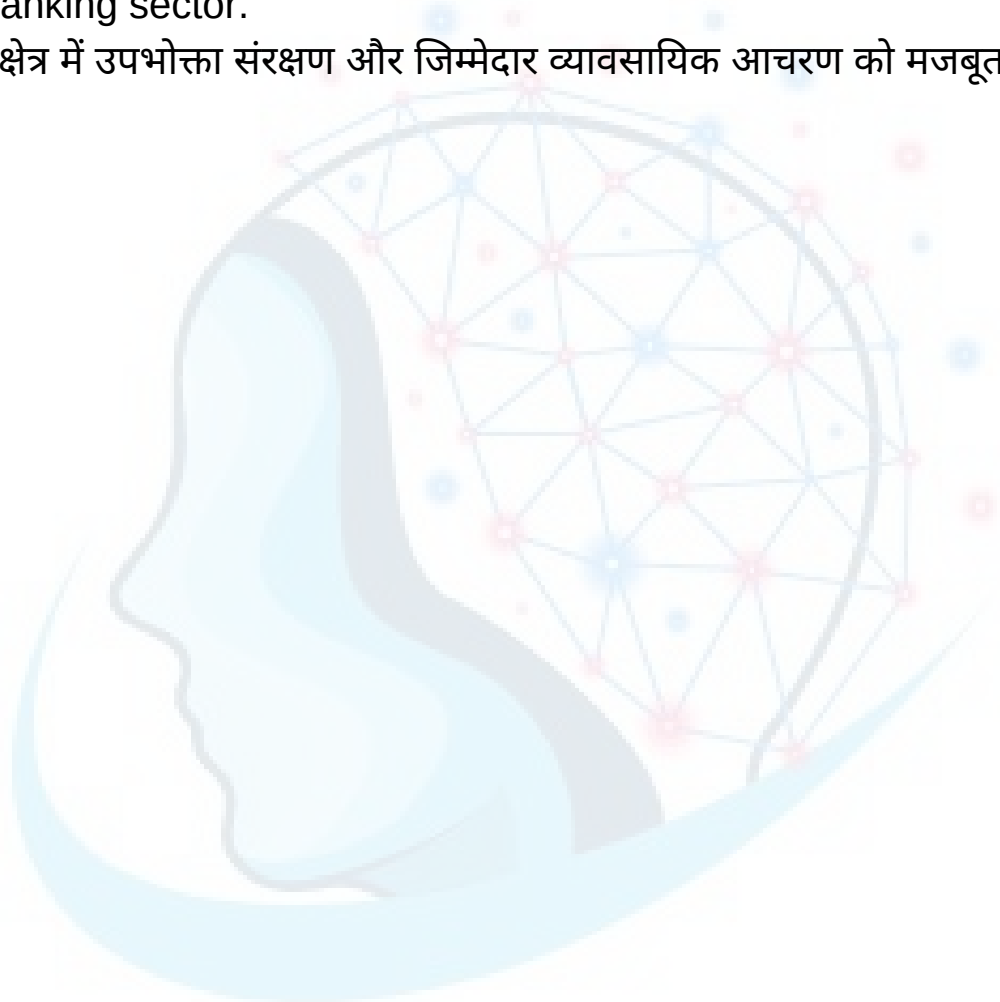
- The Reserve Bank of India (RBI) has issued comprehensive draft directions on advertising, marketing, and sales of financial products and services by banks.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों द्वारा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के विज्ञापन, विपणन और बिक्री से संबंधित व्यापक ड्राफ्ट निर्देश जारी किए हैं।
- The objective of these directions is to prevent mis-selling and compulsory bundling of financial products.
- इन निर्देशों का उद्देश्य गलत बिक्री (Mis-selling) और जबरन बंडलिंग को रोकना है।
- As per the Draft RBI (Commercial Banks – Responsible Business Conduct) Amendment Directions, 2026, banks must seek customer feedback within 30 days of sale.
- ड्राफ्ट RBI (वाणिज्यिक बैंक – जिम्मेदार व्यवसाय आचरण) संशोधन निर्देश, 2026 के अनुसार, बैंकों को बिक्री के 30 दिनों के भीतर ग्राहक से फीडबैक लेना अनिवार्य होगा।
- The new directions are scheduled to come into effect from July 1.
- ये नए निर्देश 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
- If mis-selling is established, banks must refund the entire amount paid by the customer.
- यदि गलत बिक्री साबित होती है, तो बैंक को ग्राहक द्वारा चुकाई गई पूरी राशि वापस करनी होगी।
- In addition, banks must compensate customers for any financial loss arising due to





mis-selling.

- इसके अलावा, गलत बिक्री के कारण हुए किसी भी वित्तीय नुकसान की क्षतिपूर्ति भी बैंकों को करनी होगी।
- These provisions aim to strengthen consumer protection and responsible business conduct in the banking sector.
- ये प्रावधान बैंकिंग क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण और जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण को मजबूत करने के लिए लाए गए हैं।



EXAM
Genius





Recent News Headlines Related to RBI

- Reserve Bank of India (RBI) has proposed to double the aggregate ceiling of unsecured advances for Urban Cooperative Banks (UCBs) to 20% of total assets, from the earlier limit of 10%.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए असुरक्षित ऋणों की सीमा 10% से बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव दिया है।
- Reserve Bank of India (RBI) has proposed to enhance individual and aggregate unsecured loan limits for Urban Cooperative Banks (UCBs).
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए असुरक्षित ऋण सीमाओं को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।
- Transcorp International Limited received in-principle approval from the Reserve Bank of India (RBI) to participate in Centralized Payment Systems (CPS).
- ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड को सेंट्रलाइज़्ड पेमेंट सिस्टम (CPS) में भाग लेने के लिए RBI से सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई।
- On February 6, the Reserve Bank of India (RBI) revised the GDP growth forecast for the ongoing financial year to 7.4%, up from the earlier estimate of 7.3%.
- 6 फरवरी को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने चालू वित्त वर्ष के लिए GDP वृद्धि दर का अनुमान 7.3% से बढ़ाकर 7.4% कर दिया।
- The Reserve Bank of India (RBI) has removed the overall investment cap of ₹2.5 lakh crore under the Voluntary Retention Route (VRR) for FPIs.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने FPIs के लिए VRR के तहत ₹2.5 लाख करोड़ की कुल निवेश सीमा को हटा दिया है।
- Mission SAKSHAM (Sahakari Bank Kshamta Nirman) is an initiative of the Reserve Bank of India (RBI) to strengthen Urban Cooperative Banks (UCBs).
- मिशन सक्षम (सहकारी बैंक क्षमता निर्माण) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की एक पहल है, जिसका उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को सशक्त बनाना है।
- The Reserve Bank of India (RBI) will observe Financial Literacy Week (FLW) 2026 from February 9 to 13, 2026.





Ques: Which international financial institution approved a USD 182 million loan to Assam to strengthen resilience against flooding and riverbank erosion?

असम में बाढ़ और नदी तट कटाव से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिए 182 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण किस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने स्वीकृत किया?

- A) World Bank / विश्व बैंक
- B) International Monetary Fund (IMF) / अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
- C) Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) / एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक
- D) Asian Development Bank (ADB) / एशियन डेवलपमेंट बैंक
- E) New Development Bank (NDB) / न्यू डेवलपमेंट बैंक

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- The Asian Development Bank (ADB) approved a USD 182 million loan to Assam.
- एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने असम को 182 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है।
- Objective: To expand support for strengthening Assam's resilience to chronic flooding and severe riverbank erosion along the Brahmaputra River.
- उद्देश्य: ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे लगातार बाढ़ और गंभीर नदी तट कटाव से निपटने की असम की क्षमता को मजबूत करना।
- ADB supports sustainable, inclusive, and resilient development across Asia and the Pacific.
- ADB एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सतत, समावेशी और लचीले विकास को समर्थन देता है।

About Asian Development Bank :

- Established : 19 December 1966
- HQ : Manila, Philippines
- Members : 69
- Chief Economist : Albert Park
- President : Masato Kanda





Ques: Which two institutions signed an MoU to deepen financial inclusion by providing access to mutual fund products in rural and semi-urban areas?

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में म्यूचुअल फंड उत्पादों की पहुँच बढ़ाने के लिए किन दो संस्थानों ने समझौता (MoU) किया है?

- A) Department of Posts and BSE / डाक विभाग और बीएसई
- B) Department of Posts and NSE / डाक विभाग और एनएसई
- C) RBI and NSE / आरबीआई और एनएसई
- D) SEBI and India Post Payments Bank / सेबी और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक
- E) LIC and NSE / एलआईसी और एनएसई

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

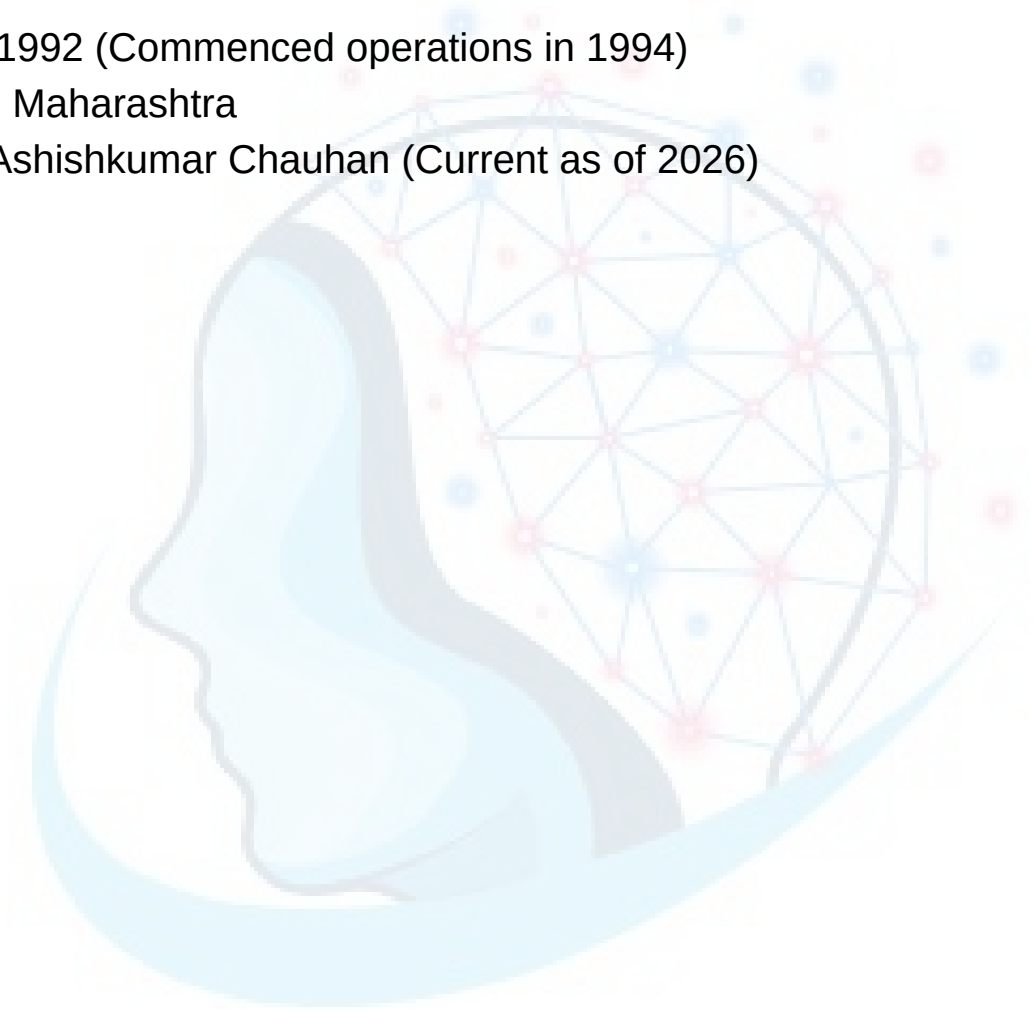
- The Department of Posts, Ministry of Communications, and the National Stock Exchange of India Limited (NSE) signed a Memorandum of Understanding (MoU) to deepen financial inclusion.
- संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता (MoU) किया है।
- The initiative aims to provide access to mutual fund products in rural and semi-urban areas.
- इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में म्यूचुअल फंड उत्पादों की पहुँच सुनिश्चित करना है।
- The partnership will leverage India Post's vast network of over 1.64 lakh post offices across the country.
- इस साझेदारी में इंडिया पोस्ट के 1.64 लाख से अधिक डाकघरों के व्यापक नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा।
- The objective is to promote transparency, investor literacy, and participation in capital market-linked products.
- इसका उद्देश्य पारदर्शिता, निवेशक साक्षरता और पूंजी बाजार से जुड़े उत्पादों में भागीदारी को बढ़ावा देना है।
- The MoU is valid for three years and can be renewed by mutual consent of both parties.
- यह समझौता तीन वर्षों के लिए वैध है और आपसी सहमति से नवीनीकृत किया जा सकता है।





National Stock Exchange :

- Established : 1992 (Commenced operations in 1994)
- HQ : Mumbai, Maharashtra
- MD & CEO : Ashishkumar Chauhan (Current as of 2026)



EXAM
Genius





RECENT LOANS AND AGREEMENTS :

- Japan's Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) has extended a USD 1 billion (₹7,100 crore) loan to the State Bank of India (SBI).
- जापान के मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप (MUFG) ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को 1 बिलियन डॉलर (₹7,100 करोड़) का ऋण प्रदान किया।
- The World Bank approved USD 830 million for India's Pradhan Mantri – Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs (PM-SETU) programme.
- विश्व बैंक ने भारत के PM-SETU (उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल एवं रोजगार परिवर्तन) कार्यक्रम के लिए 830 मिलियन अमेरिकी डॉलर स्वीकृत किए।
- The World Bank has approved a loan of ₹5,700 crore for the Jal Sanrakshit Haryana Project.
- विश्व बैंक ने जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के लिए ₹5,700 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया है।
- IREDA Global Green Energy Finance IFSC Limited (IGGEFIL) has sanctioned a USD 22.5 million loan to Swarna Solar Limited.
- इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस IFSC लिमिटेड (IGGEFIL) ने स्वर्णा सोलर लिमिटेड को 22.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है।
- The World Bank approved a loan of USD 286 million for the West Bengal Health System Reform Program (WBHSRP).
- विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम (WBHSRP) के लिए 286 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया।
- Piramal Finance Limited has received a total loan of USD 350 million.
- पिरामल फाइनेंस लिमिटेड को कुल 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्राप्त हुआ है।
- Asian Development Bank provided ₹4,100 crore (USD 500 million) to the Government of Telangana.
- एशियाई विकास बैंक ने तेलंगाना सरकार को ₹4,100 करोड़ (500 मिलियन अमेरिकी डॉलर) प्रदान किए।





Ques: What was the value of the RBI Digital Payments Index (RBI-DPI) for September 2025?

सितंबर 2025 के लिए RBI डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स (RBI-DPI) का मान क्या था?

- A) 493.22
- B) 465.33
- C) 516.76
- D) 445.50
- E) 395.57

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Reserve Bank of India (RBI) has been publishing the RBI–Digital Payments Index (RBI-DPI) since 1 January 2021, with March 2018 as the base year (Index = 100).
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) 1 जनवरी 2021 से RBI–डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स (RBI-DPI) प्रकाशित कर रहा है, जिसका आधार वर्ष मार्च 2018 (इंडेक्स = 100) है।
- The RBI-DPI for September 2025 stood at 516.76, rising from 493.22 in March 2025.
- सितंबर 2025 में RBI-DPI 516.76 रहा, जो मार्च 2025 के 493.22 से अधिक है।
- This increase reflects significant growth in digital payment adoption and performance across India.
- यह वृद्धि देशभर में डिजिटल भुगतान के उपयोग और प्रदर्शन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी को दर्शाती है।
- RBI-DPI measures the extent and depth of digitisation of payments over time.
- RBI-DPI समय के साथ डिजिटल भुगतान के विस्तार और गहराई को मापता है।
- The index is based on five broad parameters with assigned weights:
- यह इंडेक्स पाँच व्यापक मानकों और उनके निर्धारित भार पर आधारित है:
 - Payment Enablers – 25% / पेमेंट एनेबलर्स – 25%
 - Payment Infrastructure (Demand-side) – 10% / पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर (डिमांड साइड) – 10%
 - Payment Infrastructure (Supply-side) – 15% / पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर (सप्लाय साइड) – 15%
 - Payment Performance – 45% / पेमेंट परफॉर्मेंस – 45%
 - Consumer Centricity – 5% / कंज्यूमर सेंट्रिसिटी – 5%





Ques: What major regulatory change has the RBI introduced for Real Estate Investment Trusts (REITs)?

रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) के लिए RBI ने कौन-सा महत्वपूर्ण नियामकीय बदलाव किया है?

- A) RBI has allowed foreign banks to directly own REITs / RBI ने विदेशी बैंकों को REITs का प्रत्यक्ष स्वामित्व लेने की अनुमति दी है
- B) RBI has permitted banks to lend directly to REITs with prudential safeguards / RBI ने सावधानीपूर्ण सुरक्षा उपायों के साथ बैंकों को REITs को सीधे ऋण देने की अनुमति दी है
- C) RBI has removed listing requirements for REITs / RBI ने REITs के लिए लिस्टिंग आवश्यकताएँ समाप्त कर दी हैं
- D) RBI has merged REIT regulations with mutual fund norms / RBI ने REIT नियमों को म्यूचुअल फंड नियमों के साथ विलय कर दिया है
- E) RBI has restricted REIT funding only to NBFCs / RBI ने REIT फंडिंग को केवल NBFCs तक सीमित कर दिया है

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has allowed banks to lend directly to Real Estate Investment Trusts (REITs) with prudential safeguards.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सावधानीपूर्ण सुरक्षा उपायों के साथ बैंकों को REITs को सीधे ऋण देने की अनुमति दी है।
- This move aims to deepen credit access for the real estate sector and address long-term funding needs.
- इसका उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ाना और दीर्घकालिक फंडिंग की समस्या को हल करना है।
- Earlier, banks were barred from lending to REITs, though lending to Infrastructure Investment Trusts (InvITs) was permitted.
- पहले बैंकों को REITs को ऋण देने की अनुमति नहीं थी, जबकि InvITs को ऋण देना अनुमत था।
- Existing InvIT lending norms will now be harmonised with safeguards applicable to REITs.
- मौजूदा InvIT ऋण मानदंडों को अब REIT सुरक्षा उपायों के अनुरूप बनाया जाएगा।





- Currently, India has five listed REITs:
 - Brookfield India Real Estate Trust
 - Embassy Office Parks REIT
 - Mindspace Business Parks REIT
 - Nexus Select Trust
 - Knowledge Realty Trust
- Earlier, REITs largely relied on short-term bonds (3–5 years) subscribed by mutual funds, NBFCs, and others, leading to long-term funding challenges.
- पहले REITs मुख्यतः अल्पकालिक बॉन्ड (3–5 वर्ष) पर निर्भर थे, जिससे दीर्घकालिक वित्तपोषण की समस्या उत्पन्न होती थी।

EXAM
Genius





Ques: Which organisations signed an agreement to enable UPI-based cross-border merchant payments between India and Malaysia?

भारत और मलेशिया के बीच UPI-आधारित क्रॉस-बॉर्डर मर्चेट भुगतान सक्षम करने के लिए किन संगठनों ने समझौता किया?

- A) RBI and Bank Negara Malaysia / आरबीआई और बैंक नेगारा मलेशिया
- B) NPCI and Maybank / NPCI और मेबैंक
- C) NPCI International Payments Limited and Payments Network Malaysia (PayNet) / NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और पेमेंट्स नेटवर्क मलेशिया (PayNet)
- D) SEBI and CIMB Bank / सेबी और सीआईएमबी बैंक
- E) SBI and RHB Bank / एसबीआई और आरएचबी बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- NPCI International Payments Limited (NIPL) has signed an agreement with Payments Network Malaysia Sdn Bhd (PayNet).
- NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने पेमेंट्स नेटवर्क मलेशिया Sdn Bhd (PayNet) के साथ समझौता किया है।
- The agreement aims to enable QR-based cross-border merchant payments between India and Malaysia.
- यह समझौता भारत और मलेशिया के बीच QR-आधारित क्रॉस-बॉर्डर मर्चेट भुगतान को सक्षम बनाने के लिए है।
- In the first phase, Indian travellers visiting Malaysia can scan DuitNow QR codes using Unified Payments Interface (UPI) enabled apps.
- पहले चरण में, मलेशिया जाने वाले भारतीय यात्री UPI-सक्षम ऐप्स से DuitNow QR को स्कैन कर भुगतान कर सकेंगे।
- This will allow seamless merchant payments directly through UPI apps at DuitNow QR acceptance points.
- इससे DuitNow QR स्वीकार करने वाले व्यापारियों को सीधे UPI ऐप के माध्यम से सहज भुगतान संभव होगा।
- The move strengthens India's global digital payments footprint and promotes UPI as a cross-border payment solution.





Ques: Which two institutions signed an agreement to enable cashless Ayurveda treatment under general health insurance in India?

भारत में सामान्य स्वास्थ्य बीमा के तहत कैशलेस आयुर्वेद उपचार सक्षम करने के लिए किन दो संस्थानों ने समझौता किया?

- A) Ministry of AYUSH and IRDAI / आयुष मंत्रालय और IRDAI
- B) AIIMS New Delhi and General Insurance Council / एम्स नई दिल्ली और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल
- C) AIIA New Delhi and General Insurance Council / अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) नई दिल्ली और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल
- D) NITI Aayog and LIC / नीति आयोग और एलआईसी
- E) National Health Authority and GIC / राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और GIC

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- All India Institute of Ayurveda (AIIA), New Delhi and the General Insurance Council (GIC) signed an agreement to integrate Ayurveda into India's mainstream health insurance ecosystem.
- अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA), नई दिल्ली और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (GIC) ने आयुर्वेद को भारत की मुख्यधारा स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था में शामिल करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- The agreement enables cashless treatment facilities for eligible Ayurveda-based healthcare services across all 32 general insurance companies in India.
- इस समझौते के तहत देश की सभी 32 सामान्य बीमा कंपनियों में पात्र आयुर्वेद आधारित उपचारों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध होगी।
- This move is a major step toward mainstreaming traditional medicine and improving patient access to alternative healthcare systems.
- यह पहल पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को मुख्यधारा में लाने और रोगियों की पहुँच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- AYUSH stands for Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha, and Homoeopathy.
- AYUSH का अर्थ है — आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी।
- The Ministry of AYUSH was established on 9 November 2014 to promote education,





research, and development of India's traditional systems of medicine.

- आयुष मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर 2014 को भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के विकास, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- For the first time, the Government of India(GoI) has launched a dedicated Ayush Health Insurance Helpline '1800-11-0008' to support beneficiaries
- भारत सरकार ने पहली बार आयुष स्वास्थ्य बीमा के लाभार्थियों की सहायता के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन '1800-11-0008' शुरू की है।

About All India Institute of Ayurveda :

- Established : 2015
- HQ : New Delhi
- Director : Pradeep Kumar Prajapati

About General Insurance Council :

- Established : 1957
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : Tapan Kumar Singhel

EXAM
Genius



Recently signed banking agreements

- Indian Army and IDFC FIRST Bank have signed a Memorandum of Understanding (MoU) to provide specialised banking services and enhanced insurance benefits to serving and retired Army personnel.
- भारतीय सेना और IDFC फर्स्ट बैंक ने सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को विशेष बैंकिंग सेवाएँ और बेहतर बीमा लाभ देने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- Tripura Gramin Bank (TGB), in collaboration with its sponsor bank Punjab National Bank (PNB), launched a co-branded RuPay credit card.
- त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (TGB) ने अपने प्रायोजक बैंक पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के सहयोग से सह-ब्रांडेड RuPay क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया।
- Equitas Small Finance Bank (Equitas SFB) signed a strategic bancassurance partnership with Bharti AXA Life Insurance, backed by Bharti Enterprises and France's AXA, to expand the reach of life insurance across India.
- इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक (इक्विटास एसएफबी) ने भारती एंटरप्राइजेज और फ्रांस की एक्सए द्वारा समर्थित भारती एक्सए लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक रणनीतिक बैंकाश्योरेंस साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य भारत भर में जीवन बीमा की पहुंच का विस्तार करना है।
- Central Bank of India (CBI) has signed a distribution agreement with HSBC Asset Management (India) Private Limited.
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) ने HSBC एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ वितरण समझौता किया है।
- The Department of Posts (DoP), Ministry of Communications, Government of India, signed an agreement with Stock Holding Services Limited (SSL) to promote access to regulated capital market services for citizens across the country.
- भारत सरकार के संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग (DoP) ने नागरिकों के लिए विनियमित पूंजी बाज़ार सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड (SSL) के साथ समझौता किया है।
- SMFG India Credit (SMICC) has partnered with Google Pay to offer collateral-free personal loans to users across India.
- एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट (एसएमआईसीसी) ने गूगल पे के साथ साझेदारी की है ताकि भारत भर के उपयोगकर्ताओं को बिना किसी गारंटी के व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध कराया जा सके।



Ques: Which initiative was flagged off to promote AI awareness under the National AI Literacy programme “Yuva AI for All”?

राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम “युवा एआई फॉर ऑल” के तहत एआई जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई?

- A) DigiShakti / डिजीशक्ति
- B) Kaushal Rath / कौशल रथ
- C) AI Pathshala / एआई पाठशाला
- D) Bharat AI Bus / भारत एआई बस
- E) Tech Saksham / टेक सक्षम

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY), in collaboration with All India Society for Electronics and Computer Technology (AISECT), flagged off Kaushal Rath, an AI awareness initiative.
- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने ऑल इंडिया सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी (AISECT) के सहयोग से कौशल रथ नामक एआई जागरूकता पहल की शुरुआत की।
- Kaushal Rath is part of the National AI Literacy programme “Yuva AI for All.”
- कौशल रथ राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम “युवा एआई फॉर ऑल” के अंतर्गत शुरू किया गया है।
- The initiative aims to expand access to foundational AI education and bridge the digital divide, especially in semi-urban and underserved regions.
- इस पहल का उद्देश्य एआई की बुनियादी शिक्षा तक पहुँच बढ़ाना और अर्ध-शहरी व वंचित क्षेत्रों में डिजिटल खाई को पाटना है।
- Kaushal Rath is a fully equipped mobile computer lab with internet-enabled systems, audio-visual tools, and structured training modules.
- कौशल रथ एक पूर्णतः सुसज्जित मोबाइल कंप्यूटर लैब है, जिसमें इंटरनेट-सक्षम सिस्टम, ऑडियो-विजुअल उपकरण और संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल उपलब्ध हैं।
- It will travel to schools, colleges, ITIs, and community spaces to provide hands-on exposure to AI and Generative AI tools, supported by trained facilitators and contextualised Indian use-cases.
- यह स्कूलों, कॉलेजों, आईटीआई और सामुदायिक स्थलों पर जाकर एआई और जनरेटिव एआई टूल्स का





Ques: What was the allocation made to the Department of Telecommunications (DoT) in the Union Budget 2026–27 to revive telecom infrastructure and strengthen BSNL?

केंद्रीय बजट 2026–27 में दूरसंचार अवसंरचना के पुनरुद्धार और BSNL को मजबूत करने के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) को कितनी राशि आवंटित की गई?

- A) ₹53,398.17 crore
- B) ₹73,990.94 crore
- C) ₹80,927.94 crore
- D) ₹81,005.24 cror
- E) ₹69,000 crore

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Union Budget 2026–27 allocated ₹73,990.94 crore to the Department of Telecommunications (DoT), focusing on telecom infrastructure revival and strengthening Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL).
- केंद्रीय बजट 2026–27 में दूरसंचार अवसंरचना के पुनरुद्धार और BSNL को सशक्त बनाने के लिए दूरसंचार विभाग को ₹73,990.94 करोड़ आवंटित किए गए।
- The FY27 allocation is 8.65% lower than the FY26 Budget Estimate of ₹81,005.24 crore, but 38.56% higher than the FY26 Revised Estimate of ₹53,398.17 crore.
- वित्त वर्ष 2027 का यह आवंटन FY26 के बजट अनुमान से 8.65% कम, लेकिन संशोधित अनुमान से 38.56% अधिक है।
- The total net allocation for DoT in FY27 stands at ₹80,927.94 crore, including an additional ₹6,937 crore from the Universal Service Obligation Fund (USOF).
- FY27 में DoT का कुल शुद्ध आवंटन ₹80,927.94 करोड़ है, जिसमें USOF से ₹6,937 करोड़ शामिल हैं।
- Union Minister for Communications Jyotiraditya Scindia stated that the government is strengthening BSNL's financial and operational position, with ARPU rising from ₹90 to ₹99 and a target of ₹100.
- केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि सरकार BSNL की वित्तीय और परिचालन स्थिति को मजबूत कर रही है, जिसमें ARPU ₹90 से बढ़कर ₹99 हो गया है और लक्ष्य ₹100 है।





Ques: What was a key outcome of Prime Minister Narendra Modi's visit to Malaysia?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा का एक प्रमुख परिणाम क्या था?

- A) Signing of 11 bilateral agreements across multiple sectors / कई क्षेत्रों में 11 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर
- B) Launch of a joint space mission / संयुक्त अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत
- C) Announcement of a free trade agreement / मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा
- D) Establishment of a common currency / साझा मुद्रा की स्थापना
- E) Suspension of palm oil imports / पाम ऑयल आयात का निलंबन

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- During Prime Minister Narendra Modi's visit to Kuala Lumpur, India and Malaysia signed 11 important agreements covering trade, technology, digital payments, and security.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुआलालंपुर यात्रा के दौरान भारत और मलेशिया ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, भुगतान और सुरक्षा से जुड़े 11 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
- Both sides agreed to expand bilateral trade beyond USD 18.6 billion and enhance investments, signalling a new phase in the India–Malaysia partnership.
- दोनों देशों ने 18.6 अरब डॉलर से अधिक व्यापार बढ़ाने और निवेश को प्रोत्साहित करने पर सहमति जताई, जो भारत–मलेशिया साझेदारी के नए चरण को दर्शाता है।
- Leaders appreciated cooperation between the Reserve Bank of India and Bank Negara Malaysia to promote invoicing and payments in Indian Rupee and Malaysian Ringgit.
- भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंक नेगारा मलेशिया के बीच रुपये और रिंगgit में भुगतान व इनवॉइसिंग को बढ़ावा देने के सहयोग की सराहना की गई।
- Malaysia reaffirmed its commitment as a reliable supplier of sustainable palm oil to India.
- मलेशिया ने भारत को टिकाऊ पाम ऑयल का विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बने रहने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।



Recent News Headlines Related to MoU and agreement:

- Indian Pharmacopoeia Commission (IPC) signed three major MoUs to enhance drug safety, pharmacovigilance, and healthcare quality standards across India.
- भारतीय औषधि आयोग (IPC) ने भारत में दवा सुरक्षा, फार्माकोविजिलेंस और स्वास्थ्य गुणवत्ता मानकों को मजबूत करने के लिए तीन महत्वपूर्ण MoU पर हस्ताक्षर किए।
- The Government of Himachal Pradesh signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Geotropy India Private Limited to explore and harness the state's geothermal energy potential.
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की भू-तापीय ऊर्जा क्षमता के अन्वेषण और उपयोग के लिए जियोट्रोपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
- Raksha Rajya Mantri Sanjay Seth will lead Indian delegation to Saudi Arabia for the 3rd World Defence Show at Saudi Arabia. Mr. Sanjay seth will inaugurate the first-ever India Pavilion at WDS, spread over an area of 400 square meters will showcase india's capabilities in defence.
- रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सऊदी अरब में आयोजित होने वाले तीसरे विश्व रक्षा शो में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। श्री संजय सेठ विश्व रक्षा शो में 400 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैले पहले भारतीय पवेलियन का उद्घाटन करेंगे, जिसमें रक्षा क्षेत्र में भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा।
- National Test House signed MoU with STQC Directorate - Electronics Regional Test Laboratory (North) for drone testing. Drones will undergo Electromagnetic Interference (EMI) and Electromagnetic Compatibility (EMC) testing, which will strengthen India's drone testing and certification ecosystem.
- नेशनल टेस्ट हाउस ने ड्रोन परीक्षण के लिए एसटीक्यूसी निदेशालय - इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (उत्तर) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ड्रोनों का विद्युतचुंबकीय हस्तक्षेप (ईएमआई) और विद्युतचुंबकीय संगतता (ईएमसी) परीक्षण किया जाएगा, जिससे भारत के ड्रोन परीक्षण और प्रमाणन तंत्र को मजबूती मिलेगी।
- India's defence minister "Rajnath Singh" and Greece's minister of national defence "Nikolaos Georgios Dendias" signed MOU for Greece's 'Agenda 2030' aims at modernising its armed forces and defence industry.
- भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ग्रीस के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री निकोलाओस जॉर्जियोस डेंडियास ने ग्रीस के 'एजेंडा 2030' के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य उसकी सशस्त्र सेनाओं और रक्षा



Ques : Bodhan AI was launched to build which open-source digital public infrastructure?

बोधन AI किस ओपन-सोर्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए लॉन्च किया गया है?

- A) National AI Stack / राष्ट्रीय AI स्टैक
- B) India Digital Learning Grid / इंडिया डिजिटल लर्निंग ग्रिड
- C) Bharat EduAI Stack / भारत EduAI स्टैक
- D) EduTech India Network / एडुटेक इंडिया नेटवर्क
- E) National Education AI Portal / राष्ट्रीय शिक्षा AI पोर्टल

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Dharmendra Pradhan, Union Education Minister, launched Bodhan AI at the Bharat Bodhan AI Conclave.
- केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत बोधन AI कॉन्क्लेव में बोधन AI का शुभारंभ किया।
- Bodhan AI has been set up as a non-profit organisation under the Ministry of Education.
- बोधन AI को शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया है।
- The primary objective of Bodhan AI is to develop an open-source Bharat EduAI Stack as digital public infrastructure (DPI).
- बोधन AI का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ओपन-सोर्स भारत EduAI स्टैक का निर्माण करना है।
- The Bharat EduAI Stack will integrate artificial intelligence across all levels of education, helping personalise learning, support teachers, and improve governance in education.
- भारत EduAI स्टैक शिक्षा के सभी स्तरों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत करेगा, जिससे सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी।
- The initiative aims to make education more equitable, affordable, and accessible, empowering students and assisting teachers with AI-driven tools.
- यह पहल शिक्षा को अधिक समान, किफायती और सुलभ बनाने के साथ-साथ छात्रों को सशक्त और शिक्षकों को तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी।





Ques: Under the Companies Act, 2013, what does Corporate Social Responsibility (CSR) require eligible companies to do?

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के अंतर्गत पात्र कंपनियों को क्या करना अनिवार्य है?

- A) Donate 5% of annual turnover to the government / वार्षिक टर्नओवर का 5% सरकार को दान करना
- B) Spend at least 2% of average net profits on social development projects / औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% सामाजिक विकास परियोजनाओं पर खर्च करना
- C) Invest only in government-identified CSR projects / केवल सरकार द्वारा चिन्हित CSR परियोजनाओं में निवेश करना
- D) Contribute a fixed amount of ₹10 crore every year / हर वर्ष ₹10 करोड़ की निश्चित राशि देना
- E) Spend CSR funds only through government agencies / CSR राशि केवल सरकारी एजेंसियों के माध्यम से खर्च करना

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- In the last five financial years (2019–20 to 2023–24), Indian companies spent over ₹1,44,159 crore on Corporate Social Responsibility (CSR) activities.
- पिछले पांच वित्तीय वर्षों (2019–20 से 2023–24) में भारतीय कंपनियों ने ₹1,44,159 करोड़ से अधिक CSR गतिविधियों पर खर्च किए हैं।
- All CSR-related data (state-wise, project-wise, and company-wise) is publicly available on the MCA21 Portal.
- CSR से संबंधित सभी आंकड़े (राज्यवार, परियोजनावार और कंपनीवार) MCA21 पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।

What is CSR? (2% Rule) | CSR क्या है? (2% नियम)

- As per Section 135(5) of the Companies Act, 2013, certain large companies are mandatorily required to contribute to social development.
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार, बड़ी कंपनियों के लिए समाज कल्याण में योगदान देना अनिवार्य है।





- Eligible companies must spend at least 2% of their average net profits of the previous three financial years on CSR activities.
- पात्र कंपनियों को पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% CSR पर खर्च करना होता है।
- If a company's CSR obligation is ₹10 crore or more, it must appoint an independent agency for Impact Assessment.
- यदि किसी कंपनी की CSR देनदारी ₹10 करोड़ या उससे अधिक है, तो उसे स्वतंत्र एजेंसी से इम्पैक्ट असेसमेंट कराना अनिवार्य है।
- Impact Assessment evaluates projects costing ₹1 crore or more and completed at least one year earlier to assess real outcomes.
- इम्पैक्ट असेसमेंट उन परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है जिनकी लागत ₹1 करोड़ या उससे अधिक हो और जो कम से कम एक वर्ष पहले पूरी हो चुकी हों।
- The government does not allocate CSR funds; companies independently choose projects from Schedule VII areas like education, healthcare, poverty alleviation, and environmental sustainability.
- सरकार CSR फंड का आवंटन नहीं करती; कंपनियां अनुसूची VII में दिए गए क्षेत्रों—जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण संरक्षण—में स्वयं परियोजनाएं चुनती हैं।
- The MCA21 portal is an e-governance initiative of the Ministry of Corporate Affairs providing a single window for company filings, registrations, and statutory compliance.
- MCA21 पोर्टल, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की एक ई-गवर्नेंस पहल है, जो कंपनी फाइलिंग, पंजीकरण और वैधानिक अनुपालन के लिए एकल मंच प्रदान करती है।

FY 2019-20 to FY 2023-24 are as follows:

- FY 2019-20 : 24,965.82
- FY 2020-21 : 26,210.95
- FY 2021-22 : 27,141.45
- FY 2022-23 : 30,932.08
- FY 2023-24 : 34,908.75





Ques: The Union Ministry of Home Affairs plans to compile a standard English medical dictionary under which policy?

गृह मंत्रालय किस नीति के तहत एक मानक अंग्रेज़ी मेडिकल शब्दकोश तैयार करने की योजना बना रहा है?

- A) National Health Policy 2017 / राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017
- B) National Education Policy 2020 / राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
- C) National Digital Health Mission / राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन
- D) National Skill Development Policy / राष्ट्रीय कौशल विकास नीति
- E) Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan / राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Union Ministry of Home Affairs (MHA) plans to compile a standard English medical dictionary under the National Education Policy (NEP) 2020.
- केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत मानक अंग्रेज़ी मेडिकल शब्दकोश तैयार करेगा।
- The dictionary will be translated into 15 Indian languages to promote medical education in mother tongues.
- चिकित्सा शिक्षा को मातृभाषा में बढ़ावा देने के लिए इस शब्दकोश का 15 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा।
- It will include at least 1,00,000 unique medical terms along with explanatory words.
- इसमें कम से कम 1,00,000 विशिष्ट चिकित्सा शब्द और उनके व्याख्यात्मक शब्द शामिल होंगे।
- The Department of Official Language (DoL) under MHA has invited bids from reputed international publishers to compile the dictionary titled "Medical Shabd Sindhu."
- MHA के अधीन आधिकारिक भाषा विभाग (DoL) ने "मेडिकल शब्द सिंधु" नामक शब्दकोश के संकलन हेतु प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों से निविदाएँ आमंत्रित की हैं।
- In the first phase, translations will be done in Hindi, Telugu, Assamese, Gujarati, Kashmiri, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Tamil, Bengali, Manipuri, Mizo and Konkani.
- पहले चरण में हिंदी, तेलुगु, असमिया, गुजराती, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओड़िया, पंजाबी, तमिल, बंगाली, मणिपुरी, मिजो और कोंकणी भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा।





Recent Penalties imposed on Banks:

- The Competition Commission of India imposed a penalty of ₹27.38 crore on Intel Corporation.
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने इंटेल कॉर्पोरेशन पर ₹27.38 करोड़ का जुर्माना लगाया।
- The Directorate General of Civil Aviation (DGCA) imposed a ₹22.20 crore fine on IndiGo Airlines due to large-scale flight delays and cancellations in early December.
- नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने दिसंबर की शुरुआत में बड़े पैमाने पर उड़ान देरी और रद्दीकरण के कारण इंडिगो एयरलाइंस पर ₹22.20 करोड़ का जुर्माना लगाया।
- In FY25 / CY25, the Reserve Bank of India (RBI) imposed monetary penalties totalling about ₹16.28 crore on private sector banks for various regulatory and compliance violations.
- FY25 / CY25 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने विभिन्न विनियामक और अनुपालन उल्लंघनों के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों पर कुल लगभग ₹16.28 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया।
- The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) imposed a penalty of ₹1 crore on Care Health Insurance following a remote inspection.
- बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने रिमोट निरीक्षण के बाद केयर हेल्थ इंश्योरेंस पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया।
- The Reserve Bank of India (RBI) imposed regulatory restrictions on two Urban Cooperative Banks—The Gauhati Cooperative Urban Bank Limited in Assam and The Valsad Mahila Nagrik Sahakari Bank Limited in Gujarat.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने दो शहरी सहकारी बैंकों—असम स्थित गौहाटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड और गुजरात स्थित वलसाड महिला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड—पर नियामकीय प्रतिबंध लगाए हैं।
- The Reserve Bank of India imposed a monetary penalty of ₹99.30 lakh on Jammu and Kashmir Bank Limited.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड पर ₹99.30 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
- RBI imposed a penalty of ₹91 lakh on HDFC Bank for violations related to the Banking Regulation Act and deficiencies in statutory and regulatory compliance.





Ques: Which Indian space-tech startup signed a landmark agreement with Singapore's Defence Science and Technology Agency (DSTA) to protect satellites from space debris?

किस भारतीय स्पेस-टेक स्टार्टअप ने अंतरिक्ष मलबे से उपग्रहों की सुरक्षा के लिए सिंगापुर की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी (DSTA) के साथ ऐतिहासिक समझौता किया?

- A) Skyroot Aerospace / स्काईरूट एयरोस्पेस
- B) Agnikul Cosmos / अग्निकुल कॉसमॉस
- C) Digantara Industries / दिगंतरा इंडस्ट्रीज़
- D) Pixxel / पिक्सेल
- E) Bellatrix Aerospace / बेलेट्रिक्स एयरोस्पेस

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Digantara Industries, a Bengaluru-based space-tech startup, signed a landmark agreement with Defence Science and Technology Agency (DSTA).
- बेंगलुरु स्थित स्पेस-टेक स्टार्टअप दिगंतरा इंडस्ट्रीज़ ने सिंगापुर की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी (DSTA) के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- This partnership is historic as it marks the first formal collaboration between Singapore's defence establishment and an Indian space-tech company.
- यह साझेदारी ऐतिहासिक है क्योंकि यह पहली बार है जब सिंगापुर के रक्षा तंत्र ने किसी भारतीय स्पेस-टेक कंपनी के साथ औपचारिक सहयोग किया है।
- The collaboration focuses on developing tools to protect national satellites from the growing threat of space debris and orbital congestion.
- इस सहयोग का उद्देश्य अंतरिक्ष मलबे और कक्षीय भीड़ से राष्ट्रीय उपग्रहों की सुरक्षा के लिए उपकरण विकसित करना है।
- Digantara will provide services such as satellite tracking and conjunction screening to issue alerts when a satellite is at risk of collision with debris.
- दिगंतरा उपग्रह पथ ट्रैकिंग और कंजक्शन स्क्रीनिंग जैसी सेवाएँ प्रदान करेगा, ताकि टकराव की आशंका होने पर चेतावनी जारी की जा सके।
- The partnership follows Digantara's successful \$50 million Series B funding round led by Reliance Business Ventures.





Ques: Why did the Directorate General of Civil Aviation (DGCA) impose a ₹1 crore fine on Air India?

डीजीसीए ने एयर इंडिया पर ₹1 करोड़ का जुर्माना क्यों लगाया?

- A) For flight delay issues / उड़ान में देरी के कारण
- B) For safety violations by pilots / पायलटों द्वारा सुरक्षा उल्लंघन के कारण
- C) For operating an aircraft without valid airworthiness certification / वैध एयरवर्थिनेस प्रमाणन के बिना विमान संचालित करने के कारण
- D) For overcharging passengers / यात्रियों से अधिक शुल्क लेने के कारण
- E) For baggage mishandling / सामान प्रबंधन में त्रुटि के कारण

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Directorate General of Civil Aviation (DGCA) imposed a ₹1 crore penalty on Air India.
- नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर इंडिया पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया।
- The fine was imposed for operating an Airbus A320neo aircraft without valid airworthiness certification.
- यह जुर्माना वैध एयरवर्थिनेस प्रमाणन के बिना एयरबस A320 नियो विमान संचालित करने के कारण लगाया गया।
- The aircraft was reportedly operated on at least eight routes last year without proper certification.
- बताया गया है कि पिछले वर्ष इस विमान को कम से कम आठ मार्गों पर बिना उचित प्रमाणन के संचालित किया गया।
- Air India stated that the incident was voluntarily reported in 2025 and that all identified gaps have been addressed.
- एयर इंडिया के अनुसार, इस घटना की सूचना 2025 में स्वेच्छा से दी गई थी और सभी कमियों को दूर कर लिया गया है।
- DGCA is the regulatory authority responsible for civil aviation safety and compliance in India.
- DGCA भारत में नागरिक उड्डयन की सुरक्षा और अनुपालन के लिए जिम्मेदार नियामक प्राधिकरण है।





Ques: What is the key change introduced by the Ex-servicemen Amendment Rules, 2026?

पूर्व सैनिक संशोधन नियम, 2026 के तहत प्रमुख बदलाव क्या किया गया है?

- A) Introduction of new pension benefits for ex-servicemen / पूर्व सैनिकों के लिए नई पेंशन सुविधाएँ शुरू की गईं
- B) Inclusion of paramilitary forces under the ex-servicemen category / अर्धसैनिक बलों को पूर्व सैनिक श्रेणी में शामिल किया गया
- C) Official inclusion of the Military Nursing Service (MNS) under the definition of ex-servicemen / मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (MNS) को आधिकारिक रूप से पूर्व सैनिक की परिभाषा में शामिल किया गया
- D) Increase in reservation percentage for Group 'A' services / ग्रुप 'A' सेवाओं में आरक्षण प्रतिशत बढ़ाया गया
- E) Abolition of age relaxation for ex-servicemen / पूर्व सैनिकों के लिए आयु छूट समाप्त की गई

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Government has notified the Ex-servicemen Amendment Rules, 2026 under Constitution of India – Article 309, effective from 9 February 2026.
- सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत पूर्व सैनिक संशोधन नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं, जो 9 फरवरी 2026 से प्रभावी हैं।

Core Change | मुख्य बदलाव :

- Rule 2(c)(i) has been amended to explicitly include the Military Nursing Service (MNS) within the definition of “Ex-servicemen.”
- नियम 2(c)(i) में संशोधन कर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (MNS) को औपचारिक रूप से “पूर्व सैनिक” की परिभाषा में शामिल किया गया है।
- MNS is now listed alongside the Regular Army, Navy, and Air Force.
- अब MNS को नियमित थल सेना, नौसेना और वायु सेना के साथ सूचीबद्ध किया गया है।
- The provision applies to all personnel, in any rank, whether combatants or non-combatants.





- यह प्रावधान सभी रैंकों में सेवा देने वाले कर्मियों पर लागू होगा, चाहे वे कॉम्बैटेंट हों या नॉन-कॉम्बैटेंट।

Why This Matters | यह क्यों महत्वपूर्ण है :

- Earlier, there was ambiguity regarding the eligibility of MNS officers (who are commissioned officers) for ex-servicemen benefits.
- पहले यह स्पष्ट नहीं था कि MNS अधिकारी (जो कमीशंड ऑफिसर होते हैं) पूर्व सैनिक लाभों के पात्र हैं या नहीं।
- The amendment removes this ambiguity and officially recognizes MNS personnel as veterans.
- यह संशोधन इस भ्रम को समाप्त करता है और MNS कर्मियों को आधिकारिक रूप से पूर्व सैनिक का दर्जा देता है।
- This strengthens their rehabilitation prospects and second-career opportunities in the civil sector.
- इससे नागरिक क्षेत्र में उनके पुनर्वास और द्वितीय करियर के अवसर मजबूत होते हैं।

Benefits Available to MNS Personnel | MNS कर्मियों को मिलने वाले लाभ :

- 10% reservation in Group 'C' Central Government posts.
- केंद्रीय सरकार की गुप 'C' नौकरियों में 10% आरक्षण।
- 20% reservation in Group 'D' Central Government posts.
- केंद्रीय सरकार की गुप 'D' नौकरियों में 20% आरक्षण।
- Age relaxation: Total years of military service plus 3 years can be deducted from actual age for civil job eligibility.
- आयु छूट: नागरिक नौकरियों की पात्रता के लिए कुल सैन्य सेवा अवधि + 3 वर्ष वास्तविक आयु से घटाए जा सकते हैं।
- Rule 2(c)(i) remains the defining clause for who qualifies as an ex-serviceman for re-employment benefits, now clearly including MNS.
- नियम 2(c)(i) पूर्व सैनिक की पात्रता तय करने वाला आधिकारिक प्रावधान है, जिसमें अब MNS को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।





India's Rankings in Different Indices

- Corruption Perceptions Index (CPI) : India (91st), Denmark (1st)
- भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (सीपीआई): भारत (91वां स्थान), डेनमार्क (पहला स्थान)
- The Global Soft Power Index 2026 is published by Brand Finance : india (32nd), United States (1st)
- ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत (32वां स्थान), संयुक्त राज्य अमेरिका (पहला स्थान) शामिल हैं।
- Global Innovation Index (GII) rank : : India (38th)
- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) रैंक : : भारत (38वां)
- Asia Manufacturing Index (AMI) 2026 : India (6th), China (1st)
- एशिया विनिर्माण सूचकांक (एएमआई) 2026: भारत (छठा स्थान), चीन (पहला स्थान)
- The Numbeo Safety Index 2026 was published by Numbeo : India (70th), UAE (1st)
- Numbeo द्वारा Numbeo सुरक्षा सूचकांक 2026 प्रकाशित किया गया: भारत (70वां स्थान), यूएई (पहला स्थान)
- Responsible Nations Index (RNI) : India (16th) , Singapore (1st)
- जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक (आरएनआई): भारत (16वां स्थान), सिंगापुर (पहला स्थान)
- Export Preparedness Index 2024 published by NITI Aayog : Maharashtra (1st in Large States), Uttarakhand (1st in Small States)
- नीति आयोग द्वारा प्रकाशित निर्यात तैयारी सूचकांक 2024: महाराष्ट्र (बड़े राज्यों में प्रथम स्थान), उत्तराखंड (छोटे राज्यों में प्रथम स्थान)
- Henley Passport Index 2026 : India (80th), Singapore (1st)
- हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026: भारत (80वां), सिंगापुर (पहला)
- "Top Cities for Women in India 2025" report was published by Chennai-based workplace inclusion firm Avtar : Bengaluru (1st)
- चेन्नई स्थित कार्यस्थल समावेशन फर्म अवतार द्वारा प्रकाशित "भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2025"





Ques: As per the latest guidelines issued by the Union Home Ministry, which statement regarding Vande Mataram is correct?

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार वंदे मातरम् के संबंध में कौन-सा कथन सही है?

- A) Only the first two stanzas of Vande Mataram will be sung / केवल वंदे मातरम् के पहले दो पद गाए जाएंगे
- B) Vande Mataram will be sung after the National Anthem / वंदे मातरम् राष्ट्रीय गान के बाद गाया जाएगा
- C) All six stanzas of Vande Mataram must be sung for 3 minutes 10 seconds and played before the National Anthem / वंदे मातरम् के सभी 6 पद 3 मिनट 10 सेकंड तक गाए जाएंगे और इसे राष्ट्रीय गान से पहले बजाया जाएगा
- D) Singing Vande Mataram is compulsory in cinema halls / सिनेमा हॉल में वंदे मातरम् गाना अनिवार्य है
- E) The guidelines have no relation to the anniversary of the song / इन दिशानिर्देशों का गीत की वर्षगांठ से कोई संबंध नहीं है

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Union Home Ministry (Ministry of Home Affairs) has issued fresh guidelines mandating that all six stanzas of Vande Mataram be sung at official functions and educational institutions.
- केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने आधिकारिक कार्यक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम् के सभी 6 पद गाने को अनिवार्य किया है।
- Vande Mataram was originally composed by Bankim Chandra Chatterjee, and the decision coincides with the 150th anniversary of the song's creation.
- वंदे मातरम् की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, और यह निर्णय इसके 150वें वर्ष के अवसर पर लिया गया है।
- The total duration for singing or playing the national song has been fixed at 3 minutes and 10 seconds; earlier, only the first two stanzas were commonly used.
- राष्ट्रीय गीत को गाने/बजाने की अवधि 3 मिनट 10 सेकंड तय की गई है; पहले सामान्यतः केवल दो पद ही उपयोग में थे।





- All persons present must stand in attention when the song is played; however, this rule is not compulsory in cinema halls if the song appears as part of a film or newsreel.
- गीत के दौरान सभी उपस्थित लोगों को सावधान मुद्रा में खड़ा होना होगा, लेकिन यदि यह किसी फ़िल्म या न्यूज़रील का हिस्सा हो तो सिनेमा हॉल में यह अनिवार्य नहीं है।
- The order clearly states that when both the national song and the national anthem are played, Vande Mataram will be played first, including the four stanzas removed in 1937.
- आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों होने पर पहले वंदे मातरम् बजाया जाएगा, जिसमें 1937 में हटाए गए चार पद भी शामिल होंगे।

EXAM
Genius





Ques: Which organisation signed an agreement with the Technology Development Board to develop indigenous high-pressure hydrogen storage systems?

उन्नत उच्च-दाब हाइड्रोजन भंडारण प्रणालियों के विकास के लिए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) ने किस कंपनी के साथ समझौता किया?

- A) Tata Advanced Systems Limited / टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड
- B) Larsen & Toubro Limited / लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड
- C) Reliance New Energy Limited / रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड
- D) Ashok Leyland Limited / अशोक लेलैंड लिमिटेड
- E) Gudlyf Mobility Private Limited / गुडलाइफ मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- The Technology Development Board, under the Department of Science and Technology, signed an agreement with Gudlyf Mobility Private Limited, Tamil Nadu, to provide financial assistance for the development and commercialisation of indigenous high-pressure hydrogen storage systems based on advanced composite technologies.
- प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के अंतर्गत गुडलाइफ मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड (तमिलनाडु) के साथ उन्नत कम्पोजिट तकनीक पर आधारित स्वदेशी उच्च-दाब हाइड्रोजन भंडारण प्रणालियों के विकास एवं व्यावसायीकरण हेतु वित्तीय सहायता के लिए समझौता किया।
- The technology caters to both commercial and strategic sectors.
- यह तकनीक वाणिज्यिक और रणनीतिक—दोनों क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करती है।
- Hydrogen Storage: Solutions for mobile applications (vehicles) and stationary energy systems.
- हाइड्रोजन भंडारण: मोबाइल अनुप्रयोगों (वाहनों) तथा स्थिर ऊर्जा प्रणालियों के लिए समाधान।
- UAVs (Drones): Lightweight fuel storage solutions for Unmanned Aerial Vehicles.
- यूएवी (ड्रोन): मानवरहित हवाई वाहनों के लिए हल्के ईंधन भंडारण समाधान।
- CNG & CBG: Advanced storage solutions for Compressed Natural Gas (CNG) and Compressed BioGas (CBG).
- सीएनजी व सीबीजी: संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) और संपीड़ित बायोगैस (CBG) के लिए उन्नत भंडारण समाधान।





Ques: The Defence Acquisition Council (DAC) recently approved procurement of 114 Rafale jets for which force?

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने हाल ही में 114 राफेल जेट किस बल के लिए स्वीकृत किए?

- A) Indian Navy / भारतीय नौसेना
- B) Indian Army / भारतीय सेना
- C) Indian Air Force / भारतीय वायु सेना
- D) Indian Coast Guard / भारतीय तटरक्षक बल
- E) Border Security Force / सीमा सुरक्षा बल

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Defence Acquisition Council (DAC), chaired by Rajnath Singh, granted Acceptance of Necessity (AoN) for capital acquisition proposals worth about ₹3.6 lakh crore.
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में DAC ने लगभग ₹3.6 लाख करोड़ के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) दी।
- The approval includes procurement of 114 Multi-Role Fighter Aircraft (MRFA) — Rafale jets — for the Indian Air Force (IAF).
- इस मंजूरी में भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए 114 राफेल मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद शामिल है।
- Most of the Rafale jets are expected to be manufactured in India, boosting domestic defence production under Make in India.
- अधिकांश राफेल जेट भारत में निर्मित होने की संभावना है, जिससे मेक इन इंडिया के तहत घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
- The Indian Navy has been granted AoN for six additional P-8I long-range maritime reconnaissance aircraft from the United States.
- भारतीय नौसेना को अमेरिका से 6 अतिरिक्त P-8I लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान खरीदने की मंजूरी दी गई है।
- The P-8I aircraft will enhance anti-submarine warfare, maritime surveillance, and strike capabilities.
- P-8I विमान पनडुब्बी रोधी युद्ध, समुद्री निगरानी और स्ट्राइक क्षमताओं को मजबूत करेंगे।





Ques: India and Vietnam recently deepened cooperation in which sector to promote sericulture, technical textiles, and R&D, aiming to create a new 'Silk Corridor' in Asia?

भारत और वियतनाम ने हाल ही में एशिया में एक नया 'सिल्क कॉरिडोर' विकसित करने के उद्देश्य से किस क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है?

- A) Information Technology / सूचना प्रौद्योगिकी
- B) Defence Manufacturing / रक्षा विनिर्माण
- C) Pharmaceuticals / फार्मास्यूटिकल्स
- D) Agriculture and Food Processing / कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण
- E) Textile and Sericulture / वस्त्र और रेशम उत्पादन

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- India and Vietnam deepened their textile ties through a 5-day strategic collaboration, focusing on strengthening sericulture, technical textiles, and research & development (R&D).
- भारत और वियतनाम ने 5-दिवसीय रणनीतिक सहयोग के माध्यम से रेशम उत्पादन, तकनीकी वस्त्र और अनुसंधान एवं विकास (R&D) में सहयोग को मजबूत किया।
- The collaboration aligns Central Silk Board with major Vietnamese textile industry players to drive innovation and growth.
- इस सहयोग के तहत सेंट्रल सिल्क बोर्ड को वियतनाम के प्रमुख वस्त्र उद्योग समूहों के साथ जोड़ा गया है।
- Sericulture focus: Improving silk farming practices and mulberry cultivation.
- रेशम उत्पादन पर फोकस: रेशम की खेती और शहतूत (मलबरी) की खेती में सुधार।
- Technical textiles: Development of specialised, high-tech fabrics for industrial and advanced applications.
- तकनीकी वस्त्र: औद्योगिक उपयोग के लिए उन्नत और उच्च-तकनीकी कपड़ों का विकास।
- R&D collaboration: Joint research and technology transfer, particularly in automatic silk reeling technologies.
- R&D सहयोग: विशेष रूप से स्वचालित रीलिंग तकनीक में संयुक्त अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण।
- This partnership aims to establish a modern 'Silk Corridor' in Asia, boosting textile trade, innovation, and regional value chains.





- यह साझेदारी एशिया में एक आधुनिक 'सिल्क कॉरिडोर' स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

About the Silk Corridor in Asia | एशिया में सिल्क कॉरिडोर के बारे में

- The Silk Corridor refers to the historic Silk Roads, a vast network of land and sea trade routes operating from the 2nd century BCE to the 15th century CE, linking East and West.
- सिल्क कॉरिडोर ऐतिहासिक सिल्क रोड को दर्शाता है, जो दूसरी शताब्दी ईसा-पूर्व से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले स्थल एवं समुद्री व्यापार मार्ग थे।
- The land routes extended over 6,400 km, crossing difficult terrains like the Gobi Desert and Pamir Mountains.
- स्थलीय मार्ग 6,400 किमी से अधिक लंबे थे और गोबी रेगिस्तान तथा पामीर पर्वत जैसे दुर्गम क्षेत्रों से गुजरते थे।
- A key section is the Chang'an–Tianshan Corridor, a 5,000 km UNESCO-listed route, connecting Central China to the Zhetysu region of Central Asia via Kazakhstan and Kyrgyzstan.
- इसका प्रमुख भाग चांगआन–तियानशान कॉरिडोर है, जो UNESCO विश्व धरोहर में शामिल है।
- Major trading cities included Xi'an, Samarkand, Bukhara, Merv, and Kashgar, which served as hubs for trade and cultural exchange.
- ये शहर व्यापार, विश्राम और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के प्रमुख केंद्र थे।

EXAM
Genius





Ques: Which aircraft platform is associated with Apogee Aerospace's ₹3,500 crore amphibian aircraft deal with Australia?

एपोजी एयरोस्पेस के ₹3,500 करोड़ के उभयचर विमान सौदे में कौन-सा विमान प्लेटफ़ॉर्म शामिल है?

- A) Albatross 2.0 / एल्बार्ट्रोस 2.0
- B) Twin Otter / ट्विन ऑटर
- C) Dornier 228 / डोर्नियर 228
- D) C-295 / सी-295
- E) Be-200 / बी-200

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

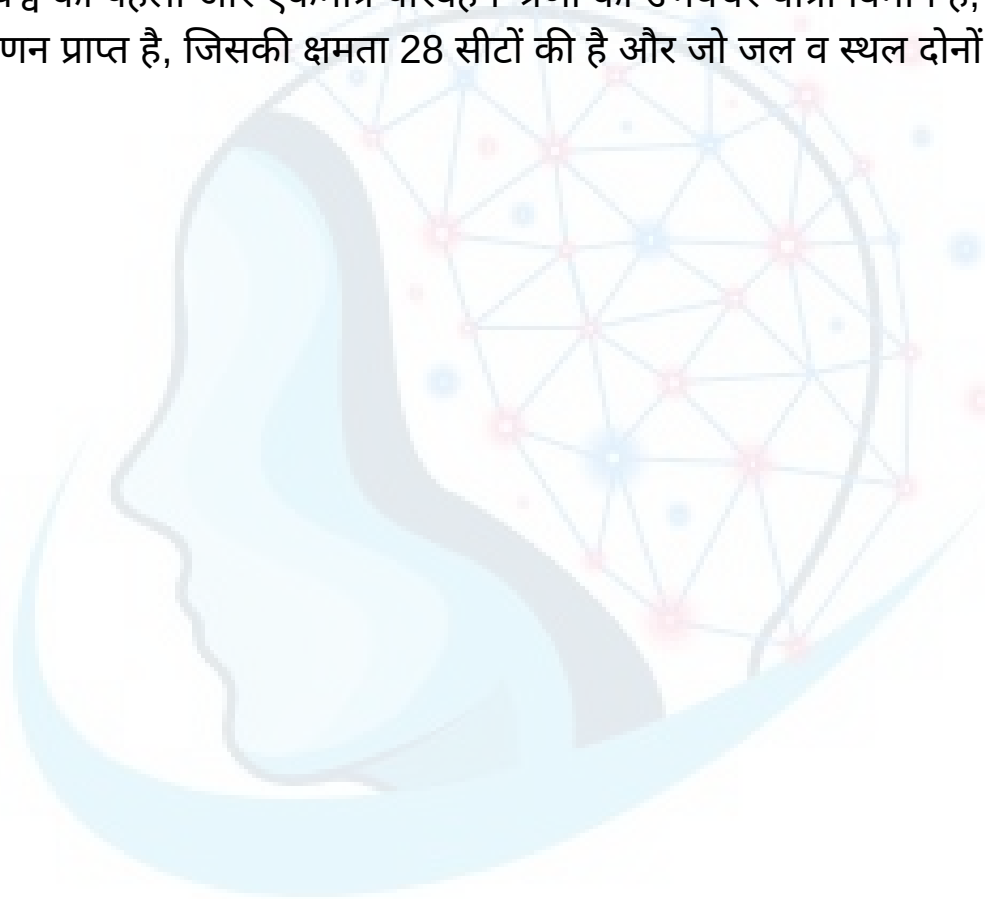
- Apogee Aerospace Private Limited placed an order worth ₹3,500 crore for 15 amphibian aircraft (seaplanes) with Amphibian Aerospace Industries (AAI).
- एपोजी एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने ऑस्ट्रेलिया की एम्फीबियन एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ 15 उभयचर विमानों के लिए ₹3,500 करोड़ का ऑर्डर दिया।
- Apogee Aerospace has become the authorized partner of AAI across the Indian subcontinent, anchored by the Albatross 2.0 platform.
- इस समझौते के तहत एपोजी एयरोस्पेस भारतीय उपमहाद्वीप में AAI का अधिकृत भागीदार बन गया है, जो Albatross 2.0 प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है।
- The partnership operates under the "Restricted Category", handling all Defence and Government aviation requirements.
- यह साझेदारी "रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी" के अंतर्गत रक्षा और सरकारी विमानन आवश्यकताओं को संभालेगी।
- Apogee Aerospace will invest ₹500 crore in India to support manufacturing and ecosystem development.
- एपोजी एयरोस्पेस भारत में निर्माण व इकोसिस्टम विकास के लिए ₹500 करोड़ का निवेश करेगा।
- About Albatross 2.0 Aircraft:
 - World's first and only transport-category amphibious aircraft in the Registered Passenger Transport segment
 - Certified by both the Federal Aviation Administration (FAA) and the European Union Aviation Safety Agency (EASA)





- Maximum capacity: 28 seats
- Capable of operating on both water and land

• Albatross 2.0 विश्व का पहला और एकमात्र परिवहन-श्रेणी का उभयचर यात्री विमान है, जिसे FAA और EASA दोनों से प्रमाणन प्राप्त है, जिसकी क्षमता 28 सीटों की है और जो जल व स्थल दोनों पर संचालन कर सकता है।



EXAM
Genius





Ques: Which state was the largest wool-producing state in India in FY24?

वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन-सा था?

- A) Jammu & Kashmir / जम्मू-कश्मीर
- B) Karnataka / कर्नाटक
- C) Rajasthan / राजस्थान
- D) Telangana / तेलंगाना
- E) Gujarat / गुजरात

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Rajasthan emerged as India's largest wool-producing state in FY24.
- FY24 में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य रहा।
- Rajasthan produced 16,013.50 thousand kg of wool, accounting for 47.53% of the country's total wool output.
- राजस्थान ने 16,013.50 हजार किलोग्राम ऊन का उत्पादन किया, जो देश के कुल उत्पादन का 47.53% है।
- Jammu & Kashmir ranked second with 7,770 thousand kg, followed by Karnataka with 6,472 thousand kg of wool production.
- जम्मू-कश्मीर 7,770 हजार किलोग्राम के साथ दूसरे और कर्नाटक 6,472 हजार किलोग्राम के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
- Telangana and Gujarat secured the fourth and fifth positions respectively.
- तेलंगाना और गुजरात क्रमशः चौथे और पाँचवें स्थान पर रहे।
- India has the second-largest sheep population in the world, with around 77.4 million sheep.
- भारत में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भेड़ आबादी है, जो लगभग 77.4 मिलियन है।
- Globally, India ranks 9th in wool production.
- वैश्विक स्तर पर ऊन उत्पादन में भारत का 9वाँ स्थान है।





Ques: Which country has been designated as the Country of the Year at BIOFACH 2026, the world's leading trade fair for organic products?

BIOFACH 2026, जो जैविक उत्पादों का विश्व का प्रमुख व्यापार मेला है, में कंट्री ऑफ द ईयर किस देश को घोषित किया गया है?

- A) Germany / जर्मनी
- B) France / फ्रांस
- C) Australia / ऑस्ट्रेलिया
- D) Brazil / ब्राज़ील
- E) India / भारत

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- India has been designated as the Country of the Year at BIOFACH 2026, marking a major global recognition in sustainable and organic agriculture.
- भारत को BIOFACH 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, जो टिकाऊ और जैविक कृषि के क्षेत्र में एक बड़ी वैश्विक उपलब्धि है।
- BIOFACH 2026 will be held from 10 to 13 February 2026 at Nuremberg, Germany.
- BIOFACH 2026 का आयोजन 10 से 13 फरवरी 2026 तक जर्मनी के नूर्नबर्ग शहर में किया जाएगा।
- India's participation is being organised by the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) under the Ministry of Commerce and Industry.
- BIOFACH 2026 में भारत की भागीदारी का आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत APEDA द्वारा किया जा रहा है।
- This recognition marks India's return to the global organic farming spotlight after 14 years.
- यह सम्मान 14 वर्षों बाद वैश्विक जैविक कृषि मंच पर भारत की सशक्त वापसी को दर्शाता है।
- The India Country Pavilion at BIOFACH 2026 will span 1,074 square metres, making it one of the largest national pavilions at the event.
- BIOFACH 2026 में भारत का कंट्री पवेलियन 1,074 वर्ग मीटर में फैला होगा, जो इस आयोजन के सबसे बड़े राष्ट्रीय पवेलियनों में से एक होगा।
- Showcase of 5 GI-tagged rice varieties: Indrayani Rice (Maharashtra), Navara Rice





Ques: What is India's rank in the 2026 Henley Passport Index?

2026 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है?

- A) 65th
- B) 70th
- C) 75th
- D) 80th
- E) 85th

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- India's passport jumped 10 places to rank 75th in the 2026 Henley Passport Index.
- भारत का पासपोर्ट 10 स्थान की छलांग लगाकर 2026 में 75वें स्थान पर पहुंच गया।
- Indian passport holders now enjoy easier or visa-free access to 56 countries worldwide.
- भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब दुनिया के 56 देशों में आसान या वीजा-मुक्त प्रवेश की सुविधा प्राप्त है।
- The improvement reflects enhanced global mobility and strengthening diplomatic relations.
- यह सुधार वैश्विक गतिशीलता में वृद्धि और मजबूत कूटनीतिक संबंधों को दर्शाता है।
- The Henley Passport Index ranks passports based on the number of destinations accessible without a prior visa.
- हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पासपोर्ट की रैंकिंग इस आधार पर करता है कि धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के जा सकते हैं

EXAM
Genius





Ques: Where will the National Large Optical–Near Infrared Telescope (NLOT) be built?

नेशनल लार्ज ऑप्टिकल–नियर इन्फ्रारेड टेलीस्कोप (NLOT) कहाँ बनाया जाएगा?

- A) Merak near Pangong Tso / पैंगोंग त्सो के पास मेराक
- B) Hanle, Ladakh / हनले, लद्दाख
- C) Kodaikanal, Tamil Nadu / कोडाइकनाल, तमिलनाडु
- D) Udaipur, Rajasthan / उदयपुर, राजस्थान
- E) Leh, Ladakh / लेह, लद्दाख

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- In the Union Budget, the Government of India approved the establishment of two new telescopes in Ladakh, along with the upgradation of an existing one.
- केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने लद्दाख में दो नए टेलीस्कोप स्थापित करने तथा एक मौजूदा टेलीस्कोप के उन्नयन को मंजूरी दी है।
- The National Large Solar Telescope (NLST) will be a 2-metre aperture solar telescope set up at Merak near Pangong Tso lake.
- नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप (NLST) 2-मीटर एपर्चर वाला सौर टेलीस्कोप होगा, जिसे पैंगोंग त्सो झील के पास मेराक में स्थापित किया जाएगा।
- Once operational in about 5–6 years, NLST will become India's third ground-based solar observatory.
- लगभग 5–6 वर्षों में संचालन शुरू होने के बाद, NLST भारत की तीसरी ग्राउंड-बेस्ड सौर वेधशाला बनेगा।
- At present, India has two operational solar observatories:
 - Kodaikanal Solar Observatory (Tamil Nadu, established in 1899)
 - Udaipur Solar Observatory (Rajasthan, established in 1975)
- वर्तमान में भारत में दो सौर वेधशालाएँ कार्यरत हैं: कोडाइकनाल (1899) और उदयपुर (1975)।
- The National Large Optical–Near Infrared Telescope (NLOT) will be a 13.7-metre segmented-mirror optical–near infrared telescope.
- नेशनल लार्ज ऑप्टिकल–नियर इन्फ्रारेड टेलीस्कोप (NLOT) 13.7-मीटर सेगमेंटेड मिरर वाला ऑप्टिकल–नियर इन्फ्रारेड टेलीस्कोप होगा।





Ques: On which date is World Radio Day observed annually?

विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है?

- A) 1 January
- B) 13 February
- C) 15 March
- D) 21 June
- E) 10 December

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- World Radio Day is observed every year on 13 February to commemorate the establishment of United Nations Radio in 1946.
- विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है, जो 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की स्मृति में है।
- The theme of World Radio Day 2026 is “Radio and Artificial Intelligence: AI is a tool, not a voice.”
- विश्व रेडियो दिवस 2026 का विषय है – “रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: AI एक उपकरण है, आवाज़ नहीं।”
- India’s first Community Radio Station was inaugurated on 1 February 2004 by Lal Krishna Advani.
- भारत का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 1 फरवरी 2004 को श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा उद्घाटित किया गया था।
- Ram Singh Bouddh from Amroha, Uttar Pradesh, popularly known as the “Radio Man of India,” was recognised by Guinness World Records in 2025.
- उत्तर प्रदेश के अमरोहा के राम सिंह बौद्ध, जिन्हें “रेडियो मैन ऑफ इंडिया” कहा जाता है, को 2025 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई।
- He owns the world’s largest collection of 1,257 radios.
- उनके पास 1,257 रेडियो का विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है।





Important days

- 25 January : National Tourism Day (Started in 1982)
- 25 January : National Voters' Day (Theme : "My India, My Vote")
- 25 January (last Sunday of January): World Leprosy Day (Theme : "Leprosy is curable, the real challenge is stigma".)
- 26 January : International Customs Day (ICD) (Theme 2026 : Customs protecting society through vigilance and commitment)
- 26 January : 3rd International Day of Clean Energy (Theme : "Clean Energy for People and Planet.")
- 27 to 30 January 2026 : 4th edition of India Energy Week (IEW) 2026
- 27 January : National Geographic Day
- 27 January : International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust, also known as International Holocaust Remembrance Day (theme for 2026 is "Holocaust Remembrance for Dignity and Human Rights.")
- 30 January : Martyrs' Day, also known as Sarvodaya Day or Shaheed Diwas (commemorates the assassination of Mahatma Gandhi on 30 January 1948)
- 30 January : National Leprosy Day
- 31 January : International Zebra Day
- 1 February : Raising Day of the Indian Coast Guard (ICG)
- 2 February : 50th World Wetlands Day (Theme 2026 Wetlands and Traditional Knowledge: Celebrating Cultural Heritage)
- 4 February : World Cancer Day (theme : "United by Unique")
- 9 February : International Epilepsy Day (Theme 2026 #EpilepsyPledge campaign)
- 10 February : 8th World Pulses Day (WPD) (theme for 2026 is "Pulses of the World: From Modesty to Excellence.")

